भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

विषयः पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबधित मार्च, 2024 माह का मासिक सारांश।

1. जल जीवन मिशन (जेजेएम)

19.65 लाख परिवारों को कार्यशील घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए, जिससे वर्ष 2023-24 के दौरान कुल संख्या 2.99 करोड़ और संचयी रूप से 14.53 करोड़ (75.3%) हो गई। 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 11 ने स्वयं को 'हर घर जल' घोषित कर दिया है। मार्च महीने के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8,240 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई, जिससे वर्ष के दौरान 70,000 करोड़ रुपये का ब.अ./सं.अ. पूरी तरह से समाप्त हो गया।

2. स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण- चरण-II

मार्च, 2024 माह के दौरान 2,67,620 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) और 1,105 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है। इस अवधि के दौरान 12,633 गांवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस घोषित किया है, जिससे संचयी संख्या 5,32,559 (सभी गांवों का 90.96%) हो गई है। 12,788 गांवों ने यह सूचित किया है कि उक्त महीने के दौरान वे ओडीएफ+ मॉडल बन गए हैं, जिससे संचयी संख्या 1,20,727 और 31.03.2024 तक 1,71,806 (29.34%) हो गई है। माह के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2,487 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इसके साथ, 7,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान का पर्याप्त रूप से उपयोग किया गया, केवल 197.42 करोड़ रुपये की राशि अप्रयुक्त रह गई।

3. गोबरधन

माह के दौरान 42 बायोगैस परियोजनाओं को कार्यशील बनाया गया, जिससे वर्ष के दौरान कार्यशील बायोगैस परियोजनाओं की संख्या 284 हो गईं और संचयी आंकड़ा 31.03.2024 तक 657 हो गया।

4. 15वें वित्त आयोग का सशर्त अनुदान

वर्ष के दौरान 15वें वित्त आयोग के सशर्त अनुदान के रूप में 23,644.22 करोड़ रुपये जारी किए गए और एफएफसी के सशर्त अनुदान के तहत जारी की गई संचयी राशि 31.02.2024 तक 1,06,120.78 करोड़ रुपये थी।

5. सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने 12 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसबीएम (जी) के चरण-2 की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों के सभी एसीएस/प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव और मिशन निदेशकों (एसबीएम-जी) के साथ बैठक की।

6. 16-17 फरवरी, 2024 को आयोजित जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसरण में, 16.03.2024 को सभी एसीएस/प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव और मिशन निदेशक-एसबीएम (जी) के साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के चिह्नित परिणामों के संबंध में आगे बढ़ने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई।

7. विदेश मंत्रालय के समन्वय में मध्य यूरोपीय (सीई) देशों के 16 देशों के 35 पत्रकारों/संपादकों वाले मीडिया प्रतिनिधिमंडल के साथ 15 मार्च 2024 को वार्ता आयोजित की गई। जल जीवन मिशन (जेजेएम) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एसबीएम (जी) के तहत हुई प्रगति को बातचीत के दौरान दर्शाया गया।

8. प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने 18 मार्च 2024 को तकनीकी समिति की एक बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की, जिसमें मूल्यांकन के लिए प्राप्त 48 प्रस्तावों में से 12 चयनित (शॉर्टलिस्ट) की गई तकनीकों पर विचार किया गया और समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद "ग्रामीण क्षेत्रों में जीआईएस नेटवर्क पर जल आपूर्ति नेटवर्क की मैपिंग के लिए वेब और मोबाइल-आधारित उपकरण" के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाने और जेजेएम नवाचार पोर्टल पर अपलोड करने की सिफारिश की गई। इसके अलावा, चल रही 8 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं (4 आईआईटी, 3 सीएसआईआर और 1 सीडब्ल्यूआरडीएम, केरल) का भी बैठक के दौरान मूल्यांकन किया गया।

9. 21.03.2024 को भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और ग्रामीण वॉश पार्टनर के फोरम के सदस्यों के साथ एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) और जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पहचान करना था। इस सत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी आभासी (वर्चुअल) रूप से भाग लिया।

10. गोबरधन के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिये 11 मार्च, 2024 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे गोबरन पोर्टल पर "अभी तक शुरू किए जाने की श्रेणी" के तहत पंजीकृत 345 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना को प्राथमिकता दें।

*****